नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 048
दि. 20.11.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई न्यायिक स्वायत्तता की कसौटी, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के प्रमुख प्रावधान किए निरस्त

(जीएनएस)। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि संसद का कानून बनाने का अधिकार सर्वशक्तिमान होते हुए भी संविधान की सीमाओं से परे नहीं जा सकता। मंगलवार को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की तीन महत्वपूर्ण धाराओं—3, 5 और 7—को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये वे ही प्रावधान हैं जिन्हें इससे पहले अदालत ने अध्यादेश के रूप में लाए जाने पर खारिज कर दिया था, और अब विधायी स्वरूप में पुनरावृत्ति किए जाने पर अदालत ने उन्हें दोबारा असंवैधानिक ठहरा कर साफ कर दिया कि न्यायिक स्वतंत्रता के मूलभूत ढांचे से कोई छेड़छाड़ स्वीकार नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विस्तृत निर्णय में कहा कि संसद यदि किसी ऐसे प्रावधान को फिर से लागू करती है जिसे अदालत पहले ही असंवैधानिक कर चुकी है, तो यह केवल तभी मान्य होगा जब वह उस खामी को दूर करे जिसकी वजह से प्रावधान रद्द हुआ था। लेकिन 2021 के कानून में न तो खामियों को दूर किया गया, न ही किसी नए संवैधानिक आधार का निर्माण किया गया। इससे पूरे कानून का स्वरूप ऐसा प्रतीत हुआ मानो अस्वीकार किए जा चुके तत्वों को एक बार फिर पुराने ढंग से लागू करने की कोशिश की गई हो। न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की टिप्पणी—"नई बोतल में पुरानी शराब"—इस पूरे विवाद का सार समाहित कर देती है।

न्यूनतम आयु 50 वर्ष, केवल चार साल का कार्यकाल और सर्च-कम-सेलेक्शन कमेटी की संरचना जैसे प्रावधान पहले ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चोट माने गए थे। अदालत ने कहा कि न्यूनतम आयु की बाध्यता युवा और सक्षम विशेषज्ञों को ट्रिब्यूनल प्रणाली से दूर करती है, जबकि छोटा कार्यकाल ट्रिब्यूनल सदस्यों को असुरक्षित बनाता है और उनकी स्वतंत्र कार्यशैली पर प्रभाव डालता है। इसके अलावा चयन समिति की संरचना कार्यपालिका को अनुचित बढ़त देकर न्यायिक निष्पक्षता को कमजोर करती है—जो कि संविधान के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के भी विपरीत है।

इस पूरे प्रकरण की जड़ 2021 में लाए गए उस कानून में है जिसकी वैधता को मद्रास बार एसोसिएशन ने चुनौती दी थी। एसोसिएशन का तर्क था कि संसद ने एक तरह से अदालत के फैसले की अवहेलना करते हुए उन्हीं प्रावधानों को फिर से लागू कर दिया जिन पर पहले ही असंवैधानिक होने की मुहर लग चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए विस्तार से यह स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल प्रणाली मूल रूप से न्यायिक ढांचे का विस्तार है, न कि कार्यपालिका की शाखा। इसलिए उसमें नियुक्तियों, सेवा शर्तों और प्रशासन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्षता और स्वायत्तता की गारंटी दे सके।

इस निर्णय ने एक बार फिर यह रेखांकित कर दिया कि ट्रिब्यूनलों की स्थापना का उद्देश्य अदालतों का बोझ कम करना और विशेषज्ञता आधारित न्याय उपलब्ध कराना है, लेकिन यदि उनकी संरचना और संचालन पर कार्यपालिका का अतिक्रमण होता है तो पूरी प्रक्रिया न्यायिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश में संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा के रूप में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह निर्णय न केवल ट्रिब्यूनलों की संरचना को नए सिरे से परिभाषित करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी कानून संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी कर दोहराव का रास्ता न अपनाए।

आर्मस्ट्रांग हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप सीबीआई जांच पर रोक से बदल गया पूरे मामले का कानूनी परिदृश्य

(जीएनएस)। तमिलनाडु की राजनीति में उथल-पुथल मचाने वाले बसपा नेता और राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग की हत्या का मामला एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के उस निर्देश पर पूरी तरह रोक लगा दी, जिसके तहत हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी और राज्य पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट को निरस्त कर दिया गया था। यह फैसला न केवल इस केस की दिशा बदलता है, बल्कि यह भी साफ कर देता है कि न्यायपालिका की विभिन्न स्तरों के बीच हस्तक्षेप की सीमाओं का निर्धारण कितनी बारीकी से किया जाना चाहिए।

जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ के समक्ष जब तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील रखी, तो अदालत ने पूरे मामले की जटिलता को देखते हुए विस्तार से सुनवाई की। इससे पहले 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केवल चार्जशीट को रद्द करने वाले हिस्से पर अंतरिम रोक लगाई थी, जबकि सीबीआई जांच को जारी रहने दिया गया था। उस समय अदालत का मानना था कि जांच की दिशा रोक देना जल्दबाजी होगी। लेकिन जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि मामले को सीबीआई को सौंपने का आधार और राज्य पुलिस की पूरी जांच पर संदेह व्यक्त करने का कारण पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं हो पाया था।

इसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक निर्णायक कदम उठाते हुए कहा कि जब तक इस अपील पर अंतिम फैसला नहीं आता, राज्य पुलिस की चार्जशीट भी यथावत मानी जाएगी और सीबीआई द्वारा जांच आगे नहीं बढ़ेगी। इस आदेश के बाद हत्याकांड से जुड़े कई पक्षों में नई कानूनी स्थिति बन गई है। एक ओर राज्य सरकार इसे अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसे और अधिकारक्षेत्र की रक्षा के रूप में देख रही है, जबकि दूसरी ओर न्यायिक समुदाय में यह चर्चा छिड़ गई है कि क्या राज्य पुलिस की जांच में अब नए सिरे से विश्वसनीयता स्थापित हो पाएगी या नहीं।

आर्मस्ट्रांग की हत्या ने जिस दिन चेन्नई की सड़कों पर सनसनी फैलाई थी, उसी दिन से यह मामला राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी विवादों का केंद्र बना हुआ है। यह हत्याकांड ऐसे समय में हुआ था जब राज्य की राजनीतिक गतिविधियाँ पहले ही तनावपूर्ण थीं, और हत्या के पीछे अपराधियों के उद्देश्यों को लेकर तरह-तरह की परतें उजागर होती रहीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य पुलिस की जांच में गंभीर कमियां हैं और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे सीबीआई को देना ज़रूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश ने यह संदेश दिया है कि केवल शंकाओं या अनुमानों के आधार पर राज्य की पूरी जांच प्रणाली को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

अब नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई में क्या रुख अपनाता है। क्या वह हाईकोर्ट के आदेश को पूरी तरह निरस्त कर देगी? क्या राज्य पुलिस की जांच को वैधता मिल जाएगी? या फिर किसी नए बीच के रास्ते की तलाश होगी? फिलहाल इतना तय है कि देश की राजनीति और न्यायिक व्यवस्था दोनों इस संवेदनशील मामले के हर मोड़ को बड़ी बारीकी से देख रही हैं।

प्राकृतिक खेती की ओर लौटने की पुकार-कोयंबटूर से प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को दिया नया मंत्र

(जीएनएस)। कोयंबटूर की हवाओं में बुधवार को एक अलग ही ऊर्जा थी। विशाल पंडालों में जुटे हजारों किसान, जैविक उत्पादों की खुशबू, मिट्टी की सुगंध और परंपरागत कृषि प्रयोगों का जीवंत प्रदर्शन—इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। मंच पर पहुंचते ही किसान समुदाय का जोश देखने लायक था। इसी मौके पर पीएम-किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भी जारी हुई, जिसके जरिए 9 करोड़ से ज्यादा किसानों तक 18 हजार करोड़ रुपये सीधे जमा हुए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री का स्वर आत्मीय भी था और चेतावनी से भरा भी। उन्होंने किसान भाइयों को समझाते हुए कहा कि खेती में रसायनों पर निर्भरता जितनी बढ़ती जा रही है, मिट्टी उतनी ही कमज़ोर होती जा रही है। उत्पादन भले कुछ समय तक बढ़ जाए, लेकिन ज़मीन की सेहत बिगड़ने पर भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए उन्होंने देश के अन्नदाताओं से आग्रह किया—पूरी ज़मीन नहीं, न पूरा साल बस "एक एकड़-एक मौसम" प्राकृतिक खेती आजमाएं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान को तुरंत सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि धीरे-धीरे प्राकृतिक पद्धति के फायदे महसूस करते हुए आगे बढ़ने का तरीका ही सुरक्षित रास्ता है। उन्होंने दक्षिण भारत की समृद्ध जैविक परंपराओं—पंचगव्य, जीवामृत, खेत में पनपती सह-फसलें, और बिना रसायन वाली खेती—को पूरे भारत के लिए आदर्श मॉडल बताया। उनके शब्दों में एक भरोसा था कि देश की परंपरा और आधुनिक शोध मिलकर भविष्य की खेती का मार्ग तय करेंगे।

कार्यक्रम स्थल पर कई कृषि वैज्ञानिक भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें संदेश दिया कि प्रयोगशालाओं की सीमाओं से बाहर निकलकर खेतों को ही 'लाइव लैब' बनाया जाए, जहाँ किसान और वैज्ञानिक मिलकर नई पद्धतियाँ खोजें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल पर्यावरण की बात नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और किसान की कमाई बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम है।

प्रधानमंत्री ने गर्व से बताया कि पिछले वर्षों में कृषि निर्यात लगभग दोगुना हो चुका है और किसान क्रेडिट कार्ड योजनाओं के जरिए किसानों को बड़ी वित्तीय शक्ति मिली है। जैविक स्टॉलों का निरीक्षण करते समय उन्होंने किसानों से बातचीत की, उनके उत्पाद देखे और कई किसानों ने उत्साह में उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं।

मंच पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि मौजूद रहे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

कोयंबटूर के 44,000 से ज्यादा किसान भी पीएम-किसान की ताज़ा किस्त के लाभार्थियों में शामिल हुए। पूरे दक्षिण भारत से आए किसानों के बीच फैली उम्मीद और आत्मविश्वास ने इस सम्मेलन को एक नए कृषि आंदोलन की शुरुआत जैसा रूप दे दिया—जहाँ मिट्टी, किसान और प्रकृति तीनों एक साथ आगे बढ़ने को तैयार दिखाई दिए।

अमेरिका से लौटे साए की गिरफ़्त अनमोल बिश्नोई की घर वापसी ने खोले अंडरवर्ल्ड के नए अध्याय

(जीएनएस)। नई दिल्ली की ठंडी सुबह में जब एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी, किसी आम यात्री को इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि उसी विमान से उतरने वाला एक व्यक्ति भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए वर्षों से सिरदर्द बना हुआ था। यह वही नाम था जिसने अंडरवर्ल्ड की परछाइयों में बैठकर सीमाओं के पार से भारत को निशाना बनाने की साजिशें बुनी थीं—अनमोल बिश्नोई, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई।

एनआईए की टीम पहले से ही एयरपोर्ट पर तैनात थी। विमान के दरवाज़े खुलते ही जिस क्षण अनमोल बाहर आया, उसी क्षण एक लंबे सफ़र का पहला पड़ाव समाप्त हुआ—वह सफ़र, जिसमें अमेरिका की धरती से उसकी गतिविधियों पर महीनों तक अंतरराष्ट्रीय निगरानी रखी गई, और फिर गुप्त सहयोग से उसे भारत भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। उतरते ही उसे हिरासत में लेना उसी अभियान का अंतिम और निर्णायक कदम था।

अनमोल कोई सामान्य आरोपी नहीं था। वह 2022 से फरार था और लॉरेंस-गोल्डी बराड़ सिंडिकेट के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण कड़ी था। मार्च 2023 में एनआईए ने अपनी चार्जशीट में विस्तार से दर्ज किया था कि 2020 से 2023 के बीच वह सिर्फ अपने भाई का साया नहीं, बल्कि कनाडा में बैठे घोषित आतंकी गोल्डी बराड़ की योजनाओं का भी मुख्य संचालक था।

कभी फोन कॉल के ज़रिये, कभी एन्क्रिप्टेड चैटों से, और कभी विदेश से भेजे गए फंडों के माध्यम से वह भारत में अपने गिरोह को निर्देश देता रहा। यह एक अदृश्य कमान थी—जिसके लक्ष्यों को, रास्तों को और धमकियों को भारत में बैठे गुर्गे निभाते थे, पर दिमाग़ सीमाओं के बाहर रहता था।

अमेरिका में छिपकर भी अनमोल की पकड़ कम नहीं हुई थी। वहाँ से वह गिरोह को ठिकाने उपलब्ध कराता रहा, हवाला-रूटों के जरिये पैसे भेजता रहा, और दिल्ली-हरियाणा-पंजाब में रंगदारी के धंधे को दूर बैठकर संचालित करता रहा। कई व्यापारी, कलाकार और कारोबारी उसके नेटवर्क की धमकियों को चुपचाप झेलते रहे—क्योंकि धमकी देने वाला व्यक्ति हज़ारों मील दूर बैठा था, पर उसकी पहुँच बेहद नज़दीक महसूस होती थी।

एनआईए की जांच RC 39/2022/एनआईए/डीएलआई सिर्फ किसी एक आरोपी को पकड़ने का मामला नहीं है। यह उस अंडरवर्ल्ड की नसें काटने की कोशिश है, जो गैंगस्टरों, आतंकियों और हथियार तस्करों की अंतरराष्ट्रीय सांठगांठ से बना है। इन कड़ियों को जोड़ने, इनके फंडिंग स्रोतों को रोकने और इनके डिजिटल ठिकानों को ध्वस्त करने का लक्ष्य इस जांच का मूल है।

अनमोल बिश्नोई अब भारत की हिरासत में है। लेकिन उसके वापस आने से एक और कहानी शुरू हुई है—उस नेटवर्क की कहानी, जो दुनिया के कई देशों की छाया में पनपता रहा और जिसे अब भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ परत-दर-परत खोलने की तैयारी में हैं।

यह प्रत्यर्पण सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उन सभी अपराधी गठजोड़ों को एक स्पष्ट संदेश है—सीमाएँ चाहे जितनी दूर क्यों न हों, कानून की पहुँच अब पहले से कहीं ज्यादा लंबी है।

सोशल मीडिया की परछाइयों में पनपता ख़तरा छत्तीसगढ़ में डिजिटल आतंक नेटवर्क का पर्दाफाश

(जीएनएस)। रायपुर की शांत गलियों और भिलाई की रोज़मर्रा की जिंदगी के बीच एक अदृश्य साया धीरे-धीरे फैल रहा था। इस साये को न किसी ने सड़क पर देखा, न किसी ठिकाने पर—यह इंटरनेट की दुनिया में सक्रिय एक खतरनाक डिजिटल जाल था, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित आईएसआईएस समर्थक हैंडलर चला रहे थे। इसी जाल में फँसाने की कोशिश दो नाबालिग लड़कों तक पहुँच चुकी थी, जिन्हें छत्तीसगढ़ की एटीएस ने बेहद गोपनीय निगरानी के बाद चिन्हित किया।

दोनों किशोरों के मोबाइल फोन जब्त किए गए तो चैट बॉक्सों में छिपी भयावह कहानियाँ सामने आईं—वीडियो, संदेश, और वह दुष्प्रचार, जिसे देखकर जांचकर्ता भी चकित रह गए। ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य हाथ ने बार-बार उन्हें उकसाने, समझाने और कट्टरपंथ की ओर धकेलने की कोशिश की। विदेशी हैंडलर उनसे स्थानीय माहौल, गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी माँगने लगे थे—यह संकेत था कि यह केवल दिमागी ज़हर नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क बनाने की कोशिश थी।

करीब डेढ़ वर्ष से खुफिया एजेंसियाँ दोनों किशोरों पर नज़र रख रही थीं। धीरे-धीरे साफ़ हुआ कि फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंटों से चल रहा यह संपर्क सामान्य बातचीत नहीं, बल्कि "डिजिटल भर्ती" की शुरुआती सीढ़ियाँ थीं। ग्रुप चैट बनाए गए, व्हाट्सऐप जैसे ऐप्स पर विचारधारा की खुराक भेजी जाती रही, और किशोरों को ऐसे रास्ते की ओर बढ़ाया जा रहा था जहाँ अंत भयावह होता है। एटीएस ने मंगलवार देर रात यूएपीए के तहत पहली एफआईआर दर्ज की। अधिकारियों के अनुसार यह मामला केवल दो किशोरों तक सीमित नहीं है—यह उस बढ़ते खतरे का संकेत है, जहाँ उंगलियों के नीचे चलने वाला मोबाइल फोन आतंकियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। उनकी भाषा नरम होती है, पर उद्देश्य बेहद कठोर—धीरे-धीरे दिमाग बदलना, स्थानीय स्थितियों की जानकारी जुटाना और राज्य में एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार कर लेना।

इस कहानी का एक और पहलू है—पहचाने गए दो किशोरों में से एक का पिता सीआरपीएफ में तैनात है। यह तथ्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए झटका था, क्योंकि यह दिखाता है कि डिजिटल कट्टरपंथ किसी भी परिवार, किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि की दीवारें लांघ सकता है।

राज्य की एटीएस अब इस पूरे नेटवर्क की परतें उधेड़ने में जुटी है—कौन-कौन इन विदेशी हैंडलरों से जुड़ चुका है, कौन संभावित निशाना है, और यह डिजिटल रास्ता आखिर किस मंज़िल की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। छत्तीसगढ़ के लिए यह मामला पहली बड़ी चेतावनी है—कि आतंकवाद अब सीमाओं से नहीं, स्क्रीन की चमक से भीतर आ रहा है; और इसकी चुप्पी ही इसका सबसे बड़ा खतरा है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

स्पष्ट कानून व सज़ा में बदलाव से समाधान

हाल ही में, दिल्ली के विजय विहार इलाके में लूट का विरोध करने वाले एक ऑटो चालक की निर्मम हत्या में पांच नाबालिगों की गिरफ्तारी गंभीर चिंता बढ़ाने वाली है। देश में नाबालिगों के बालिगों की तर्ज पर गंभीर अपराधों को अंजाम देने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं दिल्ली की घटना में गिरफ्तार किशोरों की स्वीकारोक्ति डराने वाली है कि वे नशे के आदी हैं और पैसे जुटाने के लिये लूटपाट जैसे अपराधों में लिप्त रहते हैं। यह घटना हमारे समाज में पनप रही विकृतियों की ओर इशारा कर रही है। साथ ही यह भी संकेत कि अब वक्त आ गया है कि किशोर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये सख्त कानूनों के प्रावधान हों। इसकी वजह यह है कि किशोरों को अपराध करने के बाद सामान्य जेलों में रखने के बजाय बाल सुधार गृहों में भेज दिया जाता है। लेकिन बाल सुधार गृहों में रहने के दौरान भी ऐसे अपराधी किशोरों में बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। अक्सर देखा जाता है कि बाल सुधार गृहों में रहने की सीमित अवधि के बाद कई किशोर फिर अपराधों की दुनिया में उतर जाते हैं। समाज विज्ञानियों का मानना है कि किशोर अपराधों को लेकर कानून के अस्पष्ट और लचर होने की वजह से भी दोषियों को दंडित नहीं किया जा सकता। अक्सर कहा जाता है कि नाबालिगों की सजा के मामले में अभियुक्त की उम्र को घटा दिया जाए। दरअसल, बदलते परिवेश में समय से पहले किशोरों में वयस्कों की नकारात्मक प्रवृत्तियां पनपने लगी हैं। जिसके चलते वे बड़ों के जैसे अपराध तो करते हैं। लेकिन उन्हें उस अनुपात में सजा नहीं दी जा सकती। वैसे यह भी हकीकत है कि किशोरों के सामने लंबा भविष्य होता है। यदि परिस्थितिवश या मजबूरी में वे कोई अपराध करते हैं तो उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। वैसे भी दंड का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति में सुधार ही होता है।

दरअसल, इस तथ्य पर भी विचार करने की जरूरत है कि यदि किशोर सजा काटने के बाद भी लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय रहते हैं तो उसके लिये दंड के सख्त प्रावधान होने चाहिए। वहीं, अपराध के मूल में आर्थिक विषमताएं भी हैं, जिसके चलते वे पढ़-लिख नहीं पाते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में तमाम सामाजिक विद्रूपताएं भी किशोर मन में नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। जैसेकि दिल्ली की घटना में लिप्त किशोरों ने स्वीकारा कि वे नशे के आदी हैं, यह घटना हमारे समाज में नशे के नासूर से उपजे संकट की ओर इशारा करती है। ऐसे में नशे पर अंकुश के साथ ही उन सामाजिक विसंगतियों पर नजर रखने की जरूरत है जो किशोर मन के भटकाव को जन्म देती हैं। दूसरा संकट भारतीय समाज में जीवन मूल्यों का तेजी से होता पराभव भी है। किशोरों को नैतिक शिक्षा का पाठ सही ढंग से न स्कूलों में मिल पा रहा है और न ही घरों में। इस संकट का एक बड़ा पहलू इंटरनेट पर जहरीली व अश्लील सामग्री की प्रचुरता भी है। अक्सर किशोरों व वयस्कों के अपराधों के कारण जानने पर पता चला कि उन्होंने इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देखने के बाद यौन हिंसा को अंजाम दिया। ऐसे में बच्चों को संस्कार स्कूल और घर के बजाय मोबाइल से मिल रहे हैं। इंटरनेट पर प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री को कौन और किस उद्देश्य से डाल रहा है, कहना कठिन है। लेकिन इतना तय है कि सोशल मीडिया व इंटरनेट से जुड़े विभिन्न माध्यमों में परोसी जा रही विषैली सामग्री बाल मन पर बुरा असर डाल रही है। ऐसे में नशा, अश्लीलता और अपराध उन्मुख कार्यक्रम किशोरों को अपराध की गलियों में गुजरने के लिए उकसा रहे हैं। बहरहाल, अब समय आ गया है कि नीति-नियंताओं को विचार करना चाहिए कि हत्या-बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त किशोरों के लिये कैसे कानून बनें। निश्चय ही कानून का मकसद किसी अपराधी में सुधार ही होना चाहिए। लेकिन इस छूट को सजा से छूट का हथियार बनने देने से भी रोकना चाहिए। अन्यथा किशोरों के अपराधों का सिलसिला बेकाबू हो सकता है।

मिशन-2026: माओवादी आतंक का खात्मा तय

> यानी संदेश साफ है कि नक्सलवाद-माओवाद के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति तय है। मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद-माओवाद का संपूर्ण खात्मा सुनिश्चित है। ये अभियान अपने अंतिम चरण पर है। साथ ही नक्सलवाद-माओवाद को पालने-पोसने वालों और समर्थकों के लिए कड़ी चेतावनी है।

देश सहित छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। छत्तीसगढ़ का कुख्यात माओवादी आतंकी हिडमा 18 नवंबर को मारा गया। छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षाबलों ने हिडमा की पत्नी समेत कुल 6 नक्सली-माओवादियों को ढेर कर दिया है। वस्तुतः नक्सलवाद-माओवाद के समूलनाश के पीछे केन्द्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है।जो सरेंडर करने वालों का स्वागत भी कर रही है। पुनर्वास भी सुनिश्चित कर रही है। लेकिन अगर माओवादी,आतंक का रास्ता नहीं छोड़ते तो उनका अंत भी तय है। यानी मिशन-2026 पूरी तरह से एक्टिवेट है।

17 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में रामनाथ गोयनका व्याख्यान में भी माओवादी आतंक की समाप्ति का ज़िक्र किया। अर्बन नक्सलियों और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि - "पूरे देश में नक्सलवाद-माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था। आप भी जानते हैं, बीते पांच दशकों तक देश का करीब-करीब हर बड़ा राज्य, माओवादी आतंक की चपेट में, चपेट में रहा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती-पोसती रही और सिर्फ दूर-दराज के क्षेत्रों में जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद-पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी-बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया है।"

साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरी गंभीरता के साथ देश की एकता पर गंभीर ख़तरे को भी चिन्हांकित किया। उन्होंने कहा कि - "10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली, माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी-

माओवादी कांग्रेस, MMC बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि ये मुस्लिम लीगी- माओवादी कांग्रेस, अपने स्वार्थ में देशहित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी- माओवादी कांग्रेस, देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है।"

यानी संदेश साफ है कि नक्सलवाद-माओवाद के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति तय है। मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद-माओवाद का संपूर्ण खात्मा सुनिश्चित है। ये अभियान अपने अंतिम चरण पर है। साथ ही नक्सलवाद-माओवाद को पालने-पोसने वालों और समर्थकों के लिए कड़ी चेतावनी है। अगर देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा से खेलेंगे तो अंज़ाम बुरा होगा।

वहीं छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजयशर्मा जिस तरह से नक्सलवाद-माओवाद के उन्मूलन में मिशन मोड में लगे हैं। वो क़ाबिले तारीफ़ है। माओवादी हिडमा के मारे जाने के पहले विजय शर्मा उसके गांव पूवर्ती गए थे। हिडमा की मां के साथ भोजन किया था। पुत्रवत रुप में उनका आदर सत्कार किया था। हिडमा की मां से सरेंडर करवाने के लिए अपील भी करवाई थी। इसके बाद जब हिडमा ने सरेंडर नहीं किया तो सुरक्षाबलों ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया।

2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार की वापसी होने के बाद बस्तर क्षेत्र से माओवादियों का खात्मा हो रहा है। व्यापक स्तर पर आत्मसमर्पण कराया जा रहा है। पहले 'बोली' फिर 'गोली' दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। स्थायी शांति की ओर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चेताया है चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। माओवादियों का 'अर्बन' मॉडल जिसे 'अर्बन नक्सली' के नाम से जाना जाता है। वो अभी भी देश भर में सक्रिय हैं। नई रणनीतियों पर लगा हुआ है। लेकिन ये तय है कि देश भर से नक्सलवाद-माओवादी आतंकवाद का खात्मा होगा। अर्बन नक्सलियों के ताबूत में भी अंतिम कील ठोंकी जाएगी। स्थायी शान्ति और विकास की बहाली होगी। ये नया भारत है। जो अपने नागरिकों की सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संदेश साफ है देशविरोधी कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

प्रेरणा

हजारी की हरित तपस्या की अनसुनी कथा

बिहार के एक शांत, साधारण और मिट्टी की सुगंध से भरे छोटे से गांव में हजारी नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन बिल्कुल सादा था—सुबह सूर्योदय से पहले खेत जाना, शाम को घर लौटकर मिट्टी से भरे पैरों के साथ अपने छोटे से आंगन में बैठकर शांत मन से जीवन को देखना। पर हजारी के भीतर एक ऐसी संवेदना थी जो उसे गांव के बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उसे पेड़ों से एक गहरा प्रेम था—ऐसा प्रेम जैसे कोई अपनी संतान से करता है।

गांव में अक्सर देखा जाता कि लोग घर बनाने, लकड़ी बेचने या ईंधन की जरूरत के लिए हरे-भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाते थे। हर बार जब पेड़ गिरने की आवाज आती, हजारी का दिल जैसे दरक जाता। उसे लगता जैसे किसी जीवित प्राणी की अंतिम सांस निकल रही हो। वह सोचता—ये पेड़ सिर्फ खड़े रहने वाली लकड़ी नहीं, ये हमारी सांसें हैं, हमारे भविष्य की छाया हैं, हमारे गांव की शान हैं। पर गांव वाले इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे।

एक दिन हजारी ने सोचा कि अब चुप रहना उसकी आत्मा के खिलाफ होगा। उसने गांव के लोगों को एकत्रित किया और बूढ़े बरगद के नीचे खड़े होकर बोला—"अगर हम ऐसे ही पेड़ों को काटते रहे तो एक दिन इस गांव में न छाया बचेगी, न पक्षियों का गीत, न शीतल हवा। पेड़ कटेंगे तो धरती सूख जाएगी, फसलें मर जाएंगी और हम भी। अपने ही हाथों से हम अपने भविष्य को उजाड़ रहे हैं।"

लेकिन लोगों ने उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा—"अरे हजारी, तू किसान आदमी है, बाबा नहीं बन जा। पेड़ काटना पड़ेगा तो काटेंगे, गांव इन्हीं से

चलता है।" हजारी को लोगों की उदासीनता चुभी, पर उसका संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। उसने ठान लिया कि जब दुनिया नहीं बदलेगी, तो वह खुद दुनिया को बदलने की शुरुआत करेगा।

उस दिन से हजारी ने एक व्रत ले लिया—हर दिन खेत आते-जाते कम से कम दो पौधे लगाएगा और उनकी देखभाल करेगा, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी। उसने नदी किनारे, खेत की मेड़ों पर, रास्तों के किनारे और अपने घर के आसपास पौधे लगाने शुरू कर दिए। पहले-पहल लोग उसे देखकर हंसते थे—"ये देखो, हजारी बाबा बन गया! पेड़ लगाएगा और दुनिया बचाएगा!" पर हजारी कभी नहीं डगमगाया। वह हर सुबह एक बाल्टी पानी लेकर उन पौधों के पास जाता, उनकी मिट्टी ठीक करता, सूखे पत्ते हटाता और उनसे वैसे ही बात करता जैसे कोई अपने बच्चों से करता है। दिन बीतते गए, पौधे बढ़ने लगे, और धीरे-धीरे वह स्थान हरा-भरा होने लगा। गांव वाले, जो पहले उसे पागल कहते थे, अब चुपचाप उसे देखते। कुछ युवा तो उसके पास आने लगे—"हजारी काका, हम भी आपके साथ पेड़ लगाएंगे।" हजारी की आंखों में चमक आ जाती। वह न किसी का नाम चाहता था, न प्रसिद्धि—बस धरती को सांस देता देखना चाहता था।

धीरे-धीरे उसका यह अकेला संघर्ष एक आंदोलन बन गया। गांव के युवाओं, बच्चों और यहां तक कि बुजुर्गों ने भी पौधे लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में वह बंजर रास्ता, जहां धूल उड़ती थी, अब पेड़ों की कतारों से ढका रहने लगा। छावें इतनी घनी हो गईं कि दोपहर की कड़ी धूप भी वहां लज्जा से पीछे हट जाती। पक्षी लौट आए, हवा सुगंधित हो गई, और धरती जैसे फिर से जी उठी।

लोग हजारी की मेहनत देखकर कहते—"ये तो कोई साधारण काम नहीं ये तो तपस्या है, वृक्षों की तपस्या।" और इसी तपस्या का सम्मान करते हुए गांव के लोग उस जगह को 'हजारीबाग' कहने लगे—हजारी द्वारा बनाया गया बाग, हजारी की भक्ति का स्थान।

समय बीतता गया और वही हजारीबाग आज झारखंड का एक सुंदर, प्रसिद्ध और प्रकृति की गोद में बसा पर्यटक स्थल बन चुका है। लोग दूर-दूर से आते हैं और विशाल पेड़ों की कतारें देखकर पूछते हैं—"ये सब किसने किया?" और गांव वाले मुस्कुराकर कहते हैं—"एक किसान जिसकी तपस्या ने बंजर धरती को स्वर्ग बना दिया।"

हजारी शायद अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी हर सांस उन पेड़ों में बसती है जो आज भी मजबूती से खड़े हैं, अपनी छाया और प्राणवायु से दुनिया को जीवन देते हुए। हजारी की कहानी यह याद दिलाती है कि एक अकेला इंसान भी धरती को बदल सकता है। बस उसे हिम्मत चाहिए, लगन चाहिए, और यह विश्वास कि जब मन शुद्ध हो, तो उसकी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती।

जलवायु संकट बढ़ाते विकसित देश, चुनौतियों से निपटने के लिए रहना होगा

ब्राजील के बेलम में आयोजित काप 30 सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन पर विकसित देशों की गहरी असंवेदनशीलता को ही उजागर किया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को करीब तीन दशक हो चले हैं। इस कड़ी में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर आयोजित होने वाले काप सम्मेलन अपनी भूमिका पर खरे नहीं उतर पा रहे। ये वार्षिक सम्मेलन विरोधाभासों का मंच बनकर रह गए हैं।

ऐतिहासिक रूप से दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक रहे विकसित देश स्थितियों को सुधारने के लिए शेष विश्व से अपेक्षाएं तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की तत्परता नहीं दिखा रहे। विकासशील देशों का कहना है कि उन्हें वार्षिक 1.3 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की आवश्यकता है। जबकि विकसित देशों ने 2035 तक केवल 300 अरब डालर का ही वादा किया है। इसमें भी अधिकांश राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। स्वाभाविक है कि इससे गतिरोध की स्थिति और गहराएगी।

बेलम सम्मेलन ने दर्शाया कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली उन प्रक्रियाओं और सहमति नियमों के बोझ तले दब रही है, जो कुछ देशों को मनमानी की गुंजाइश देती है। यूरोपीय संघ को ही देखें तो उसने जलवायु परिवर्तन से जुड़े वादों और उनकी पूर्ति में भारी अंतर पर विमर्श के बजाय अपने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी सीबैम को वाजिब ठहराने पर ही अधिक जोर दिया। सीबैम विकासशील देशों के लिए ग्रीन टैरिफ की तरह है, जो मुख्य रूप से यूरोपीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए तैयार किया गया है। सभी प्रमुख निर्यातकों ने चेतावनी दी है कि एकतरफा उपाय पूरी प्रणाली को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बावजूद यूरोपीय संघ संरक्षणवाद को प्राथमिकता देने में लगा है। अमेरिका की टैरिफ नीति पहले ही वैश्विक विश्वास पर आघात कर रही हैं। जलवायु कूटनीति अब व्यापार एवं भू-राजनीति के साथ टकरा रही है।

विकसित देशों के दोहरे रवैये और भू-राजनीतिक अस्थिरता के वर्तमान परिदृश्य में भारत गंभीर, न्यायसंगत और सिद्धांत आधारित राह दिखा रहा है। इस कड़ी में पहला बिंदु है समानता और जलवायु न्याय पर जोर देना। भारत ने दुनिया को स्मरण कराया कि पेरिस समझौते के स्वरूप को एकाएक नहीं बदला जा सकता। भारत ने दोहराया कि विकसित और विकासशील देशों में विकास के स्तर पर जमीन-आसमान का अंतर है और इस लिहाज से साझा उत्तरदायित्व के प्रयास को कमजोर करना भरोसे को कुंद करने का काम करेगा। इस दिशा में मांग एकदम सरल है कि जो देश पहले से और भारी मात्रा प्रदूषण करते हैं, उन्हें उत्सर्जन में कटौती के साथ ही विकासशील देशों का अपेक्षित समर्थन भी करना चाहिए। भारत ने जोर दिया है कि विकसित देशों को 2050 से बहुत पहले ही नेट जीरो यानी शून्य उत्सर्जन के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए, ताकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उचित आधार तैयार हो सके। इसके अभाव में वैश्विक जलवायु ढांचा असमानता बढ़ाने का एक माध्यम ही बनकर रह जाता है।

भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय संसाधन खैरात न होकर अनुच्छेद 9.1 के तहत एक कानूनी दायित्व है। उसने जलवायु वित्त की एक सार्वभौमिक रूप से सहमति प्राप्त परिभाषा, अनुकूलन वित्त में 15 गुना वृद्धि और पूर्वानुमानित रियायती संसाधन प्रवाह की मांग की है। इसमें अरबों नहीं खरबों डालर चाहिए होंगे। इस क्रम में भारत ने निजी वित्त या ऋण एवं भारी पैकेजों पर निर्भर रहने की भ्रांति को भी उजागर किया है। ऐसे उपाय ऋण संकट को ही बढ़ाते हैं। इसलिए वास्तविक अनुदान को वरीयता दी जानी चाहिए। दुनिया विकासशील देशों से केवल यही उम्मीद नहीं कर सकती कि वे अपनी ऊर्जा प्रणालियों को बदलें और कृषि को लचीला बनाएं। इस सबके फेर में हो यह रहा है कि विकासशील देश महंगे कर्जों का ऊंचा ब्याज चुकाने में लगे हैं।

भारत का दृष्टिकोण है कि प्रौद्योगिकी उपलब्धता एक अधिकार होना चाहिए न कि सौदेबाजी का जरिया। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जिन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, वे बौद्धिक संपदा अधिकारों की आड़ में विकासशील देशों के लिए पहुंच से बाहर हो जाती हैं। इसलिए बौद्धिक संपदा और बाजार बाधाओं को दूर किया जाए। यह तो वही स्थिति हुई कि समाधान पहले से मौजूद है, लेकिन उसकी उपलब्धता में अवरोध से समस्या को ही बढ़ाया जा रहा है। यह किसी लापरवाही से कम नहीं। भारत ने सीबैम जैसे एकतरफा जलवायु टैरिफों की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया कि ये न केवल अनुच्छेद 3.5 का उल्लंघन करते हैं, बल्कि जलवायु नीति को संरक्षणवाद के हाथों का खिलौना भी बना देते हैं। भारत ने स्पष्ट रूप से चेताया कि ऐसे उपायों से बहुपक्षीयता की भावना को चोट पहुंचती है। इनके जरिये उन देशों को निशाना बनाया जाता है, जिन्हें सतत विकास के लिए नीतिगत उपायों की आवश्यकता होती है।

जलवायु परिवर्तन की विकराल होती समस्या के समाधान में भारत की कथनी एवं करनी में भी भेद नहीं है। उसकी उपलब्धियां उसके प्रति भरोसे का निर्माण करती हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि 2005 के बाद से भारत ने उत्सर्जन की तीव्रता को 36 प्रतिशत से अधिक कम किया है और गैर-जीवाश्म क्षमता के लिए निर्धारित 2030 के लक्ष्य को पांच साल पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने 256 गीगावाट से अधिक की स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित है। हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा और जैव ईंधन में गहरी छाप छोड़ने वाले मिशन शुरू किए हैं। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से दो अरब से अधिक पेड़ लगाए हैं। वह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे कई वैश्विक मंचों के नेतृत्व से भी जुड़ा है।

कॉप के इस सम्मेलन का अभी तक यही सार सामने आ रहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की संक्रमण अवधि के बीच व्यापार युद्ध जैसी स्थितियों के साये में समृद्ध देश अपनी आवश्यक भूमिका से किनारा कर रहे हैं। जबकि भारत ने दिखाया है कि ईमानदार राह कैसी होती है। सवाल यह है कि क्या विकसित दुनिया इसे अपनाने के लिए तैयार है।

अभियान

मां दुर्गा के 108 दिव्य नामों का चमत्कारी जाप जो जीवन को पलभर में बदल देता है

हिंदू धर्म में नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को प्रकाश से भर देने वाला एक दिव्य अनुभव है। यह वह समय है जब सम्पूर्ण सृष्टि देवी शक्ति की उपासना में डूब जाती है। मां दुर्गा की आराधना प्राचीन काल से ही मानव जीवन को कष्टों से मुक्त करने वाली मानी गई है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष, विपरीत परिस्थितियाँ, मानसिक अशांति, आर्थिक तंगी या परिवार में लगातार होने वाली परेशानियों से घिर जाता है, तब उसे शक्ति के वास्तविक स्वरूप की शरण लेनी चाहिए—वह शक्ति जो जगत की जननी है, जो समस्त ब्रह्मांड की नाड़ी में स्पंदित होती है, वही शक्ति मां दुर्गा कहलाती है।

कहते हैं कि मां दुर्गा के 108 नामों का जाप केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो व्यक्ति के भाग्य, मन, बुद्धि, ऊर्जा और घर के वातावरण को पूर्ण रूप से बदल सकता है। यह जाप वह ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे व्यक्ति के भीतर का भय समाप्त होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और जीवन में अद्भुत स्थिरता आती है। प्राचीन ऋषियों ने इसे केवल मंत्र नहीं माना, बल्कि इसे जगतजननी को पुकारने का सीधा मार्ग बताया।

जो लोग प्रतिदिन मां दुर्गा के इन 108 नामों का स्मरण करते हैं, उनके मन में ऐसी दिव्य शक्ति जन्म लेती है कि वे जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी सहजता से पार कर जाते हैं। यह नाम केवल उच्चारण नहीं, बल्कि कंपन हैं। जिनके स्पंदन से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। घर में कलह हो, परिवार में असहमति हो, अचानक बाधाएं बढ़ जाएं या फिर घर के लोग लगातार बीमार रहने लगें—ऐसे समय में मां भगवती के नामों का जाप किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता।

कहते हैं कि देवी के प्रत्येक नाम में एक अद्वितीय शक्ति छिपी है। कोई नाम दुखों को हरता है, कोई संकटों को काटता है, कोई मन को शांत करता है, तो कोई जीवन में धन, सौभाग्य और संतति का आशीर्वाद प्रदान करता है। मां दुर्गा को अष्टोत्तर शतनामावली में 108 अलग-अलग रूपों में याद किया गया है—एक-एक नाम ऐसा जैसे किसी आध्यात्मिक दीपक की लौ, जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाती है।

नवरात्रि के दौरान पूरे जगत में भक्त

माता के इन नामों को स्मरण करते हैं, परंतु यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के अलावा प्रतिदिन भी अपना दिन शुरू करने से पहले कुछ क्षण निकालकर शांत मन से इन नामों का जाप करे, तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसकी किस्मत जागृत होने लगती है, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, और घर में सुख-समृद्धि की अनुभूति स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है।

पुराणों में यह भी वर्णित है कि जब किसी व्यक्ति पर ग्रहों का प्रकोप हो, जब जीवन में अनचाही घटनाएं बढ़ जाएं या मन अत्यधिक भयभीत हो—तब देवी के 108 नामों का स्मरण उस व्यक्ति के चारों ओर एक आध्यात्मिक कवच तैयार कर देता है। यह कवच उसे अदृश्य बाधाओं से बचाता है और उसके जीवन मार्ग को सुगम बनाता है। यही कारण है कि योगी, संत और गृहस्थ—सभी लोग इसे एक अत्यंत शक्तिशाली साधना मानते हैं।

यह जाप केवल बाहरी संसार को नहीं बदलता, यह मनुष्य के भीतर छिपे आत्मबल, साहस, धैर्य और ऊर्जा को भी पुनर्जीवित करता है। जब व्यक्ति देवी माता के नामों का स्मरण करता है, तब उसके भीतर वही शक्ति प्रवाहित होने लगती है जो कभी देवी ने महिषासुर, शुम्भ–निशुम्भ, चंड-मुंड और अनगिनत असुरों का विनाश करने के लिए धारण की थी। यह शक्ति साधारण नहीं—यह जीवन को पलभर में बदल देने वाली ऊर्जा है।

जो लोग कहते हैं कि उनका घर अशांत रहता है, छोटी-छोटी बातों पर कलह हो जाती है, बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर रहता है या अचानक आर्थिक समस्या से सामना हो जाता है—उन्हें यह जाप अवश्य करना चाहिए। क्योंकि यह जाप केवल घर का वातावरण ही नहीं बदलता, बल्कि घर में देवत्व को स्थापित करता है। जहां मां की कृपा निवास करती है, वहां नकारात्मकता कभी टिक नहीं पाती।

मां दुर्गा के ये 108 नाम, जिन्हें दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली कहा जाता है, स्वयं देवी की कृपा को प्रकट करने वाले दिव्य बीज हैं। कहते हैं कि जब मनुष्य बड़ी श्रद्धा के साथ इन नामों को गाता है, तो मां उसकी हर पुकार सुनती है—बिना किसी विलंब के, बिना किसी शर्त के।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

लालकिला धमाके की गूंज: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद सिद्दीक़ी 13 दिन की ईडी रिमांड पर, आतंक नेटवर्क की परतें और गहरी

(जीएनएस)। नई दिल्ली की रात अभी पूरी तरह ढली भी नहीं थी कि साकेत अदालत परिसर में हलचल तेज हो गई। घड़ी ने करीब एक बजने का संकेत दिया ही था कि ईडी की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीक़ी को कड़ी सुरक्षा में अदालत के भीतर लेकर दाखिल हुई। बाहर खड़े अफसरों की आँखों में साफ-साफ देखा जा सकता था कि मामला सिर्फ आर्थिक अपराध का नहीं, बल्कि एक ऐसे जाल का है जिसकी डोरें लालकिला विस्फोट के खून-खराबे से जुड़ चुकी हैं।

10 नवंबर को दिल्ली के दिल—लालकिला—के पास आई-10 कार में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत और 32 लोग घायल हुए थे। शुरुआत में यह मामला महज कार विस्फोट माना गया, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी पूरी तरह बदलती चली गई। डॉक्टरों का सफेदपोश नेटवर्क, विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियाँ, अवैध फंडिंग के रास्ते और तकनीक में प्रशिक्षित युवाओं का इस्तेमाल—इन सबने सुरक्षा एजेंसियों को इस नतीजे तक पहुंचा दिया कि यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ रची गई एक संगठित योजना थी।

इसी पृष्ठभूमि में, अदालत ने बुधवार को जावेद सिद्दीक़ी को 13 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। जज शीतल चौधरी प्रधान के इस फैसले ने साफ संकेत दिया कि जांच एजेंसियों के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो यूनिवर्सिटी के आर्थिक लेन-देन को सीधे आतंकी नेटवर्क से जोड़ते हैं। ईडी को संदेह है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सिर्फ शिक्षा से नहीं, बल्कि कुछ ऐसे गुप्त फंडिंग रास्तों से भी जुड़ा है जिनसे कार बम साजिश को हवा मिली।

लालकिला विस्फोट की कहानी का एक और दिल दहलाने वाला हिस्सा है जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश का किरदार। एनआईए की गिरफ्त में आए दानिश ने कथित तौर पर ड्रोन तकनीक में बदलाव किए, विस्फोट से पहले रॉकेट जैसी डिवाइस तैयार की और मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी की ब्रेनवॉशिंग का शिकार होकर पूरे मॉड्यूल का हिस्सा बना। जांच टीम को यह भी पता चला कि उमर नबी केवल एक डॉक्टर नहीं था, बल्कि कई युवा छात्रों को धर्म, तकनीक और कट्टरपंथ के संगम पर खड़ा कर आतंक की राह दिखाने वाला मास्टरमाइंड था।

एनआईए ने इससे पहले आमिर रशीद अली को 10 दिन की हिरासत में लिया था—वह वही व्यक्ति है जिसने विस्फोट में इस्तेमाल की गई आई-10 कार मुख्य आरोपी उमर को उपलब्ध कराई। यह वही कार थी, जो 10 नवंबर की उस डरावनी शाम दिल्ली की सड़कों पर मौत बनकर घूमी। आमिर का फोन रिकॉर्ड, लोगों से उसकी मुलाकातें, और कार सौंपने का तरीका—सब कुछ इस बात की गवाही देता है कि वह इस साजिश का महज एक छोटा हिस्सा नहीं, बल्कि मुख्य लॉजिस्टिक लिंक था।

इन गिरफ्तारियों के बाद जांच का फोकस अब तेजी से फंडिंग की दिशा में मुड़ चुका है। एजेंसियों का मानना है कि धमाके की योजना तैयार होने से पहले ही बड़े पैमाने पर पैसे की आवाजाही हुई थी—कभी नकद, कभी दान के नाम पर, और कभी शैक्षणिक संस्थान की आड़ लेकर। इसी रहस्यमयी आर्थिक धुंध को साफ करने के लिए ईडी को जावेद सिद्दीक़ी की रिमांड की जरूरत थी।

दिल्ली की यह रात भले ठंडी थी, लेकिन अदालत परिसर में गर्मी थी—क्योंकि हर कदम पर यह सवाल तैर रहा था कि आखिर एक यूनिवर्सिटी के भीतर ऐसा क्या चल रहा था, जो सीधे देश की राजधानी में हुए भीषण विस्फोट तक पहुँच गया? जांच एजेंसियों का कहना है कि यह कहानी अभी शुरुआत है—और जैसे-जैसे गिरफ्तार लोगों के डिजिटल फुटप्रिंट्स, बैंकिंग रिकॉर्ड, और संपर्कों की परतें खुलेंगी, एक बड़ा आतंकी इकोसिस्टम सामने आ सकता है। जावेद सिद्दीक़ी की गिरफ्तारी और उससे जुड़ी छिपी परतें इस बात की गवाही हैं कि लालकिला विस्फोट किसी एक व्यक्ति की सनक नहीं था—यह एक लंबे समय से तैयार होती योजना का चरम था। अब अगली 13 दिन की ईडी पूछताछ पर पूरे देश की नजरें होंगी, क्योंकि शायद इन्हीं दिनों में यह साफ होगा कि शिक्षा की आड़ में किस तरह राजधानी में मौत का तंत्र बुना गया।

उत्तर प्रदेश से आए पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी के लिए भारत पर्व बना एक यादगार अनुभव

एकता नगर में फूड स्टॉल से हुई अच्छी कमाई, गुजरात की संस्कृति और उद्यमिता बनी प्रेरणा

(जीएनएस)। गांधीनगर : उत्तर प्रदेश निवासी धनेश कुमार गुप्ता ने हाल ही में एकता नगर में आयोजित भारत पर्व में हिस्सा लिया था, जो उनके लिए एक यादगार अनुभव बन गया है। वे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के लाभार्थी हैं और पारंपरिक व्यंजनों का जायका लोगों तक पहुंचाते हैं। गुजरात सरकार ने उन्हें एकता नगर में आयोजित भारत पर्व में स्टॉल लगाने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे उन्हें अच्छी कमाई भी हुई है, और अब उन्हें अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी मिली है। इटावा निवासी धनेश कुमार ने भारत पर्व में लोगों को रबड़ी और स्वादिष्ट केसर दूध का स्वाद चखाया। स्वाद, शुद्धता और गुणवत्ता की कसौटी पर खरे उतरे उनके द्वारा तैयार व्यंजन देखते ही देखते लोकप्रिय बन गए और उनका स्टॉल आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। गुजरात में अपने इस पहले अनुभव के बारे में धनेश कुमार उत्साहपूर्वक बताते हैं, "भारत पर्व में शामिल होना मेरे जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक है। मुझे अपने स्टॉल पर आने वाले लोगों में विनम्रता देखने को मिली। आगंतुकों ने हमारे व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाया और उनकी प्रशंसा भी की। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए मैं गुजरात सरकार का आभारी हूं। उम्मीद है कि मैं अगले साल फिर यहां आऊंगा और गुजरात की स्वाद प्रेमी जनता को नए व्यंजनों का स्वाद चखाऊंगा।"

इस कार्यक्रम में शामिल होने से धनेश कुमार का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। भारत पर्व के दौरान उन्होंने 60 हजार रुपए की कमाई की है, जो बताता है कि स्ट्रीट वेंडर्स यानी पथ विक्रेताओं और छोटे दुकानदारों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य सकारात्मक रूप से साकार हो रहा है।

स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्व जैसे कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं, जिसमें भारत की संस्कृति और विविधतापूर्ण व्यंजनों की झलक भी दिखाई देती है। धनेश कुमार गुप्ता के लिए यह कार्यक्रम केवल एक व्यावसायिक अवसर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा यादगार अनुभव भी रहा है, जो उनकी आर्थिक सशक्तिकरण की यात्रा को और भी मजबूत एवं गौरवमय बनाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोयंबटूर से पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक की सहायता हस्तांतरित की

▸▸ पीएम-किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त से राज्य के 49.31 लाख किसानों को मिली 986 करोड़ रुपए की सहायता

▸▸ गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि के साथ ही मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के करकमलों से 11.68 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न कृषि सहायता के मंजूरी पत्रों का वितरण

▸▸ राज्य के किसानों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा

▸▸ हाल ही में हुई असाधारण बेमौसम बारिश से राज्य के किसानों को हुए नुकसान से उन्हें उबारने के लिए डबल इंजन सरकार ने बहुत ही कम समय में 10 हजार करोड़ रुपए का उदारतम राहत सहायता पैकेज दिया : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- ▸▸ प्रधानमंत्री की कृषि हितकारी नीति और किसानों के प्रति उनकी संवेदना के फलस्वरूप राज्य के 98 फीसदी से अधिक किसानों को दिन में बिजली मिल रही है
- ▸▸ प्रधानमंत्री ने बीज से लेकर बाजार तक के हर स्तर में किसानों के साथ खड़े रहकर उनका कल्याण सुनिश्चित किया है
- ▸▸ प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट चेन्ज की चुनौतियों से निपटने के लिए ग्रीन कवर बढ़ाकर सुरक्षा प्रदान करने का दृष्टिकोण अपनाया
- ▸▸ प्राकृतिक खेती भविष्य की खेती है, मिट्टी और लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक कृषि को अपनाना मौजूदा समय की मांग है

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव किसानों की चिंता करते हुए अनेक किसान-उन्मुख पहलें शुरू की हैं : कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य के किसानों पर हाल ही में आई असाधारण बेमौसम बरसात की विपदा से हुए नुकसान से उन्हें उबारने के लिए इस डबल इंजन सरकार ने बहुत ही तेजी से 10 हजार करोड़ रुपए का उदारतम सहायता पैकेज दिया है।

मुख्यमंत्री ने यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर से देश के किसानों के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने के अवसर पर गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कही। इस मौके पर राज्य के किसानों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 21वीं किस्त के अंतर्गत 18 हजार करोड़ रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित की। इस सहायता के तहत गुजरात के 49.31 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए 986 करोड़ रुपए मिले।

गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी और कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा ने पीएम-किसान सम्मान निधि के साथ ही 11.68 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न कृषि सहायताओं के मंजूरी पत्रों का वितरण किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इतना ही नहीं, क्लाइमेट चेन्ज की चुनौतियों से निपटने के लिए 'एक पेड़ मां के नाम' और प्राकृतिक कृषि जैसे अभियानों के माध्यम से ग्रीन कवर बढ़ाकर सुरक्षा प्रदान करने का दृष्टिकोण अपनाया है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन युक्त खेती से बिगड़ रहे जमीन और मानव के स्वास्थ्य को बचाने के उपाय के रूप में प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक कृषि को अपनाने का जो विचार दिया है, वह भविष्य की पीढ़ी के स्वस्थ एवं तंदुरुस्त जीवन तथा जमीन की उर्वरता बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने प्राकृतिक कृषि को भविष्य की खेती करार देते हुए कहा कि इसे अपनाना मौजूदा समय की मांग है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री बीज से लेकर बाजार तक के हर स्तर पर किसान हितकारी निर्णयों के जरिए उनके साथ खड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के बजट में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू करने का कमिटमेंट किया था, जिसे उन्होंने अन्नदाता की चिंता करते हुए 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू करके यह सिद्ध किया कि वे जो कहते हैं, वह करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कृषि हितकारी नीति एवं किसानों के प्रति संवेदना के कारण आज गुजरात के लगभग 98 प्रतिशत से अधिक किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। किसानों को पर्याप्त पानी व बिजली मिलने के कारण राज्य के कृषि क्षेत्र की तसवीर समग्रतया बदल गई है तथा किसान समृद्ध हुआ है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में 2005 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू कराए गए कृषि महोत्सव के तहत राज्य सरकार खुद चलकर किसानों के खेत में जाती है और उन्हें इसकी समझ देती है कि कौन-सी फसल लगानी चाहिए, मूल्यवर्धन करके किस तरह अधिक आय प्राप्त हो सकती है। इससे लैब टू लैंड का दृष्टिकोण भली-भांति साकार हुआ है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदा-सर्वदा किसानों की चिंता की है। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अनेक कृषि-उन्मुखी पहलें की हैं, जिसे आज राज्य के उदार एवं दृढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री वाघाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा तमिलनाडु से आज 'पीएम किसान सम्मान निधि' योजना की 21वीं किस्त का वर्चुअल माध्यम से वितरण किया गया है, जिसमें राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राम पंचायत, एपीएमसी आदि से लगभग 3 लाख किसान ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए मशीनीकरण, फसल संरक्षण, कृषि में नैनो टेक्नोलॉजी तथा आईटी का उपयोग, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती, किसानों के लिए उत्पादन बढ़ाने, खर्च घटाने व अधिक बिक्री की व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि आज दिन-प्रतिदिन हमारी कृषि भूमि बंजर होती जा रही है, जिसके कारण वर्तमान एवं भावी पीढ़ियां अनेक रोगों का शिकार न बनें; इसके लिए प्राकृतिक कृषि को अपनाना चाहिए। इसके अंतर्गत राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में मिशन मोड पर कार्य किया जा रहा है।

श्री वाघाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को उपकार भाव से नहीं, बल्कि सेवा के भाव से सम्मान देने के लिए वर्ष 2019 से 'पीएम-किसान सम्मान निधि' योजना की समग्र देश में शुरुआत कराई है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पूर्ण पारदर्शिता के फलस्वरूप किसानों के बैंक खातों में पैसा सीधे पहुंच रहा है। कृषि उत्पादों का बाजार में दाम नीचा हो, तब एमएसपी से खरीद का बड़ा निर्णय भी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। राज्य में किसानों ने 293 केंद्रों पर लगभग एक लाख मीट्रिक टन से अधिक मूंगफली पहुंचाई है। आज राज्य में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी हो चुकी है।

कृषि विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. अंजू शर्मा ने स्वागत संबोधन में कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बुवाई से बिक्री तक की योजनाएं लागू की गई हैं। सरकार संशोधित बीजों, उर्वरकों, यांत्रिक औजारों, प्राकृतिक खेती, कृषि राहत पैकेज, समर्थन मूल्य पर खरीद से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से किसानों की सहायक हो रही है। नए आई-किसान पोर्टल 2.0 पर आवेदन कर किसान अनेक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री के करकमलों से 15 किसान लाभार्थियों को कृषि, बागवानी की विभिन्न योजनाओं की सहायता का वितरण किया गया।

इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा, महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, गुजरात कृषि उद्योग निगम (जीएआईसी) के प्रबंध निदेशक श्री विजय खराडी, जिला कलेक्टर श्री मेहुल दवे, जिला विकास अधिकारी श्री बी. जे. पटेल तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनों के समय में संशोधन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे की दो जोड़ी ट्रेनों के ठहराव के समय में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है।

1. ट्रेन संख्या 10115 बांद्रा टर्मिनस - मडगाँव एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 10115 बांद्रा टर्मिनस - मडगाँव एक्सप्रेस के ठहराव का समय संशोधित कर रत्नागिरी स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 16:05/16:10 बजे के बजाय 15:35/15:40 बजे कर दिया गया है।

कणकवली स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 18:40/18:42 बजे के बजाय 18:00/18:02 बजे होगा।

सिंधुदुर्ग स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 19:00/19:02 बजे के बजाय 18:20/18:22 बजे होगा।

2. ट्रेन संख्या 19259 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ - भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 19259 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ - भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस के ठहराव का समय संशोधित कर सिंधुदुर्ग स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 12:20/12:22 बजे के बजाय 12:50/12:52 बजे कर दिया गया है।

ट्रेनों के ठहराव और समय के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर रेलवे मंडल से होकर चलने वाली 4 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे के गांधीनगर जयपुर स्टेशन के पुनर्विकास और बड़े स्तर पर उन्नयन कार्य के मद्देनजर 9 नवंबर से 13 दिसंबर, 2025 तक 35 दिनों का ब्लॉक लिया गया है, जिसके कारण भावनगर मंडल की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

1. पोरबंदर से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस तत्काल प्रभाव से 12 दिसंबर, 2025 तक परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी स्टेशनों के रास्ते चलाई जाएगी और यह ट्रेन रींगस, नीम का थाना और नारनौल स्टेशनों पर रूकेगी।
2. पोरबंदर से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 20937 पोरबंदर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस 09 दिसंबर, 2025 तक परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी स्टेशनों के रास्ते चलाई जाएगी और यह ट्रेन रींगस, नीम का थाना और नारनौल स्टेशनों पर रुकेगी।
3. दिल्ली सराय रोहिल्ला से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 20938 दिल्ली सराय रोहिल्ला-पोरबंदर एक्सप्रेस 24 नवंबर, 2025 से 8 दिसंबर, 2025 तक परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा स्टेशनों के रास्ते चलाई जाएगी और यह ट्रेन नारनौल, नीम का थाना और रींगस स्टेशनों पर रुकेगी।
4. 25 नवंबर, 2025 को अयोध्या कैंट से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19202 अयोध्या कैंट-भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया भरतपुर-कोटा-आणंद-अहमदाबाद-विरमगाम स्टेशनों के रास्ते चलाई जाएगी और यह ट्रेन सवाई माधोपुर, कोटा, भवानी मंडी, शामगढ़, नागदा, रतलाम, दाहोद, गोधरा और आणंद स्टेशनों पर रुकेगी।

जेल की दीवारों के भीतर छिपा अंधेरा: कोट भलवाल की उच्च सुरक्षा बैरकों में काउंटर इंटेलिजेंस का बड़ा धावा, आतंकी नेटवर्क की परतें उधड़ने लगीं

(जीएनएस)। जम्मू की कड़ी सुरक्षा में ढकी हुई सुबह आज अचानक हलचल से भर उठी, जब काउंटर इंटेलिजेंस की विशेष टीमों ने चुपचाप कोट भलवाल जेल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ना शुरू किया। यह वही जेल है, जहाँ देश के सबसे कुख्यात अपराधियों, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों और घाटी के कई हार्डकोर मिलिटेंट्स को कठोर सुरक्षा में रखा जाता है। लेकिन आज हालात कुछ अलग थे—जेल की ऊँची दीवारों के भीतर जो खामोशी फैली थी, वह इस बात का संकेत दे रही थी कि कोई बड़ा अभियान शुरू हो चुका है।

जैसे ही पुलिस की विशेष टीमें जेल प्रबंधन को आदेश दिखाकर भीतर दाखिल हुईं, परिसर में तनाव की लकीरें फैल गईं। निरीक्षण के लिए भेजी गई इकाइयों के पास साफ इनपुट था कि जेल के अंदर से एक संगठित आतंकी नेटवर्क अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है—एक ऐसा नेटवर्क, जो सिर्फ फोन कॉल या चिट्ठियों से नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया में होने वाले विस्फोटों तक को निर्देशित करने में भूमिका निभा सकता है। हाल में डॉक्टरों के एक समूह द्वारा चलाए जा रहे सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश और 10 नवंबर को दिल्ली के लालकिले के पास कार में हुए विस्फोट की जांच ने इस शक को और मजबूत कर दिया था।

कोट भलवाल जेल का नाम पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है—यहाँ बंद कई पाकिस्तानी आतंकियों पर हिंसक झड़पों, उकसावे और छिपे संदेशों के जरिये जेल के भीतर अपने गुट मजबूत करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बार हालात कहीं ज्यादा गंभीर बताए जा रहे थे। काउंटर इंटेलिजेंस को इनपुट मिला था कि बाहरी आतंकवादी संगठनों के साथ जेल के अंदर बैठे कुछ कैदियों की गुप्त संचार श्रृंखला सक्रिय हो चुकी है। ये संपर्क किस तरह बनाए गए, किसने किसको सुविधा दी, और कौन-सा संदेश कहाँ तक पहुँचाया गया—इन्हीं जवाबों की तलाश में आज की पूरी छापेमारी केंद्रित थी।

जेल के अंदर कई बैरकों में सामान खंगाले गए—कैदियों के बिस्तरों, निजी कपड़ों, वॉशरूम के अंदरूनी हिस्सों, किताबों में छिपे नोट्स और यहां तक कि खाद्य सामग्री की पैकिंग तक की सख़्त जांच की गई। कई जगहों पर मिले छोटे-छोटे कागज़, हस्तलिखित कोड, संदिग्ध चिह्न और कुछ डिजिटल टुकड़े इस बात का संकेत दे रहे थे कि जेल के भीतर एक लंबे समय से चल रही छिपी गतिविधि पर किसी ने चुपचाप काम किया है।

अधिकारियों के अनुसार, यह सिर्फ एक रूटीन सर्च नहीं थी—यह एक व्यापक और योजनाबद्ध रैकेट को जड़ से उखाड़ने की शुरुआत है। दिल्ली के लालकिला क्षेत्र में कार विस्फोट की गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है, और जांच एजेंसियों को शक था कि किसी कैदी ने इस घटना से जुड़े व्यक्तियों को सलाह या निर्देश जेल के भीतर से भेजे हो सकते हैं। इसी शक ने कोट भलवाल पर त्वरित और कठोर कार्रवाई को जन्म दिया। जेल के बाहर तैनात सुरक्षा संसाधनों को बढ़ा दिया गया है। अंदर की कई बैरकें सील कर दी गईं, और कुछ कैदियों को अस्थायी अलगाव में रखा गया है।

वडोदरा मंडल ने भारतीय रेलवे पर पहली बार ई-नीलामी नवाचार के माध्यम से "अपनी तरह का पहला" वेयरहाउसिंग अनुबंध किया

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल के वाणिज्य विभाग ने गैर-किराया राजस्व (नॉन फेयर रिवेन्यू) पहल को उल्लेखनीय बढ़ावा देते हुए, भारतीय रेलवे पर पहली बार ई-नीलामी नवाचार के माध्यम से एक वेयरहाउस सुविधा के लिए "अपनी तरह का पहला" अनुबंध सफलतापूर्वक किया है। इस पहल के तहत वडोदरा स्टेशन पार्सल कार्यालय के पास पहले से खाली पड़े स्थान की पहचान कर, उसका प्रभावी सदुपयोग किया गया और एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति को रेलवे के लिए एक आकर्षक राजस्व स्रोत में बदल दिया गया।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंडल के वाणिज्य विभाग ने यह उपलब्धि ई-नीलामी मॉड्यूल में एक विशेष श्रेणी के निर्माण के माध्यम से हासिल की गई। इस तरह के नवाचार से भारतीय रेलवे में अधिक लचीले परिसंपत्ति मुद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। इस अनुबंध का मूल्य तीन वर्षों की अवधि के लिए 24.33 लाख रुपये है, जो रेलवे के अपने संसाधनों के मुद्रीकरण को अधिकतम करने के उद्देश्य की दिशा में एक सफल कदम है। यह समर्पित वेयरहाउसिंग सुविधा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करती है, जिससे पार्सल यातायात की अधिक मात्रा आकर्षित होने की उम्मीद है। स्टेशन पर एक निर्दिष्ट भंडारण क्षेत्र उपलब्ध कराने से, प्लेटफार्मों पर पार्सल पैकेजों के रखने में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी। साथ ही वडोदरा स्टेशन पर पहले से खाली पड़े क्षेत्र की साफ़ - सफाई भी बेहतर ढंग से हो सकेगी, जिससे रेलवे के रखरखाव की लागत में कमी आएगी। इस स्थान के उपयोग से अनधिकृत अतिक्रमणों और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और समग्र स्टेशन सुरक्षा में वृद्धि होगी। यह पहल प्रभावी स्थान प्रबंधन के लिए एक आदर्श उदाहरण है।

आधार कार्ड का नया युग: अब सिर्फ फोटो और सिक्योर QR कोड, दिसंबर से पहचान सुरक्षित करने की सबसे बड़ी पहल

(जीएनएस)। देश में पहचान से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरने वाली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI आधार कार्ड को पूरी तरह नई संरचना में लाने की तैयारी में है—ऐसी संरचना, जिसमें ना आधार नंबर दिखाई देगा, ना पता, ना जन्मतिथि और ना ही कोई अतिरिक्त विवरण। कार्ड पर केवल व्यक्ति की एक फोटो होगी और उसके साथ एक अत्यधिक सुरक्षित QR कोड। यह QR कोड वह डिजिटल चाबी बनेगा, जिसके माध्यम से पहचान की पुष्टि सीधे UIDAI से जुड़े सिस्टम पर होगी।

ये व्यवस्था उस लंबे समय से जारी चिंता का समाधान बनकर उभर रही है, जिसमें आधार की फोटोकॉपी के दुरुपयोग की संभावनाएँ हमेशा चर्चा में रही हैं। UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने हाल ही में एक ऑनलाइन सम्मेलन में स्वीकार किया कि फोटोकॉपी आधारित पहचान प्रक्रिया आज सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में उभर चुकी है। होटल, सिम विक्रेता, इवेंट आयोजक, ऑफिस या कोई भी संस्था आधार की कॉपी अपने पास रख लेती है और कई बार यह दस्तावेज़ अनजाने में या जानबूझकर गलत जगहों तक पहुँच सकता है। आधार

की सुरक्षा के जिस मजबूत उद्देश्य से यह प्रणाली बनाई गई थी, वर्षों में वही व्यवस्था डेटा रिस्क और संभावित दुरुपयोग का साधन बनने लगी। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया था कि आधार कार्ड को एक ऐसी पहचान में बदला जाए जिसे देख कर कोई भी व्यक्ति या संस्थान निजी जानकारी तक पहुंच न सके। नया आधार कार्ड इसी सोच का विस्तार है—एक ऐसा कार्ड जिसमें कागज़ पर कोई जानकारी न लिखी हो जिसे पढ़कर किसी की पहचान, पता या जन्मतिथि का अनुमान लगाया जा सके। QR कोड ही सबकुछ बताएगा और उसे पढ़ने के लिए सिर्फ UIDAI के प्रमाणित ऐप या उपकरण ही काम आएंगे। इसका सीधा मतलब है कि किसी दुकान, होटल या कार्यालय को आधार दिखाने भर से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि कार्ड पर पढ़ने लायक कुछ लिखा ही नहीं होगा। अगर उन्हें किसी की पहचान सत्यापित करनी है, तो उन्हें प्रमाणित ऐप से QR को स्कैन करना होगा, जो केवल यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति वही है जो कह रहा है—दूसरी कोई निजी जानकारी नहीं।

यूआईडीएआई इस नई प्रणाली को दिसंबर 2025 से लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही धीरे-धीरे ऑफलाइन वेरिफिकेशन यानी फोटोकॉपी आधारित पहचान का तरीका खत्म किया जाएगा। यह देश के पहचान ढाँचे में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि अब पहचान पूरी तरह डिजिटल सत्यापन पर आधारित होगी। QR कोड न केवल पहचान को सुरक्षित बनाएगा बल्कि फर्जी दस्तावेज़ बनाने वालों की संभावनाएँ भी लगभग समाप्त कर देगा। कागज़ पर कोई भी जानकारी ना छपी होने से नकली आधार तैयार करना लगभग असंभव हो जाएगा।

इस बदलाव का एक बड़ा प्रभाव सामाजिक मानसिकता पर भी पड़ेगा। आज कोई भी दस्तावेज़ अगर कागज़ पर छपी जानकारी के साथ आता है तो लोगों में एक विश्वास पैदा करता है—मानो वह असली हो। नया आधार इस सोच को तोड़ देगा। अब पहचान का मतलब कागज़ पर छपी सूचनाएँ नहीं, बल्कि सुरक्षित डिजिटल सत्यापन होगा। यह बदलाव न केवल तकनीकी उन्नति है बल्कि लोगों को अपनी ही पहचान पर अधिक नियंत्रण देने की दिशा में उठाया गया कदम भी है। इन सुधारों के केंद्र में वही एक बड़ी चिंता है—किसी नागरिक की निजी जानकारी किसी भी कीमत पर गलत हाथों में न जाए। UIDAI का यह प्रयास पहचान सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने वाला हो सकता है, और संभव है कि आने वाले वर्षों में दुनिया के अन्य देश भी इसी मॉडल को अपनाने की ओर कदम बढ़ाएं।

सीकर में खौफ़नाक मंजर: नवजात के अंग नोचकर ले गया कुत्ता, गली में घूमते देख दहल उठे लोग

(जीएनएस)। राजस्थान के सीकर में सोमवार की शाम एक ऐसा भयावह दृश्य सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। आनंद नगर कॉलोनी की शांत गलियों में अचानक चीख-पुकार तब मच गई जब लोगों ने एक आवारा कुत्ते को अपने जबड़ों में एक नवजात के शरीर को दबाए हुए इधर-उधर भटकते देखा। कुत्ते के मुंह में छोटी-सी निर्जीव देह थी, जिसका आकार और हालत देखकर किसी का भी दिल दहल उठे।

स्थानीय निवासी पहले तो अवाक रह गए, फिर हिम्मत जुटाते हुए उन्होंने तुरंत उद्योग नगर थाना पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों की मदद से कुत्ते से नवजात का शरीर छुड़वाया गया। लेकिन तब तक दृश्य इतना दर्दनाक बन चुका था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। पुलिस के अनुसार यह एक पूर्ण रूप से विकसित नवजात लड़के का भ्रूण था। कुत्ता उसे किसी सुनसान जगह से उठा लाया था और संभवतः रास्ते में ही उसने उसके हाथ और पैर नोचकर अलग कर दिए थे। पुलिस को घटना स्थल के आसपास से बच्चे का दाहिना हाथ और पैर भी बरामद हुए।

और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि नवजात की नाभि पर कॉर्ड क्लैंप लगा हुआ मिला—यह वह उपकरण है जो अस्पतालों में प्रसव के बाद नाल काटकर लगाया जाता है। इस एक निशान ने पूरी घटना को और संदिग्ध बना दिया। इससे यह आशंका गहराती है कि बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही कहीं—किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में—छोड़ दिया गया होगा। पहचान छिपाने के डर या किसी अन्य कारण से उसे लावारिस अवस्था में फेंक दिया गया, जहां कुत्ते ने उसे उठा लिया। उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि कॉल शाम 5 से 6 बजे के बीच मिली थी। पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया और सभी सबूत एकत्र किए। नवजात के अवशेषों को एसके अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है।

अब पुलिस एक-एक सुराग को जोड़ने में जुटी है—कौन था नवजात? उसे किसने और क्यों फेंका? किस अस्पताल या नर्सिंग होम में उसका जन्म हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या यह हत्या है, गर्भपात का मामला है या जन्म के बाद जानबूझकर छोड़ा गया नवजात?

इलाके में दहशत और आक्रोश दोनों है। लोग इस क्रूर घटना को समझ पाने की स्थिति में नहीं हैं। हर कोई यही पूछ रहा है कि मां-बाप आखिर किस मजबूरी या बेरहमी में ऐसे मासूम को यूं मौत के हवाले कर सकते हैं।

पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल पूरे शहर में एक ही सवाल गूंज रहा है—कौन है वह जिसने जन्म लेते ही इस मासूम की जिंदगी छीन ली?

अंतरराष्ट्रीय कड़ी टूटने की शुरुआत: अमेरिका ने लौटाया अनमोल बिश्नोई, भारत में NIA ने पहली ही रात कसा शिकंजा

(जीएनएस)। मुंबई और दिल्ली के बीच बुधवार की हलचल किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम जैसी नहीं थी, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह दिन एक निर्णायक मोड़ बन गया। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और उसके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिना जाने वाला अनमोल बिश्नोई अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लाया गया, और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारते ही NIA ने उसे घेरे में ले लिया। यह वही व्यक्ति है, जिसकी छाया पिछले कई सालों से बॉलीवुड, पंजाब की राजनीति और मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बीच घूमती रही—कभी सलमान खान के घर फायरिंग में, कभी बाबा सिद्दीकी की हत्या में और कभी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के साए में।

अमेरिका ने हाल ही में 200 लोगों को डिपोर्ट किया है। उनमें 3 भारतीय भी शामिल थे—दो पंजाब से और एक अनमोल बिश्नोई। बाकी दो भारतीयों की पहचान उजागर नहीं

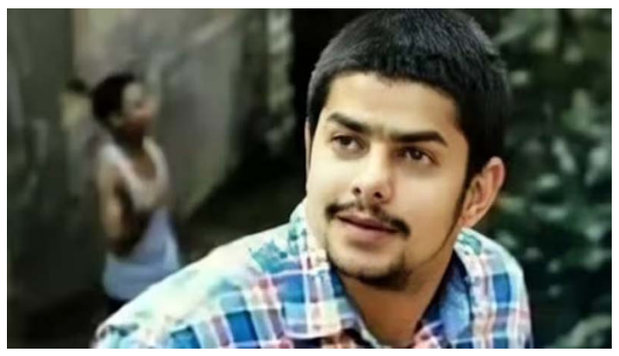

हुई है, लेकिन अनमोल का नाम आते ही भारतीय सुरक्षा तंत्र में अचानक हलचल बढ़ गई। एयरपोर्ट पर NIA की टीम पहले से मौजूद थी। एक ऐसा चेहरा, जिसने पिछले कुछ वर्षों में सीमा पार बैठे गैंगस्टरों और देसी अपराधियों के बीच पुल का काम किया, अब पहली बार सीधे भारतीय कानून के सामने खड़ा था। उसे तुरंत पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, जहां अदालत ने उसे 11 दिन की NIA कस्टडी में भेज दिया—यह एक छोटी अवधि नहीं, बल्कि उन सवालों की लंबी सूची का संकेत था जो NIA उसके सामने खोलने वाली है।

अनमोल की कहानी केवल एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि तीन महाद्वीपों तक फैले उस नेटवर्क की कहानी है जिसकी डोरें कभी कनाडा में गोल्डी बराड़ के पास थीं, कभी पंजाब की जेलों में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के पास और कभी अमेरिका में अवैध तरीके से घुसकर छिपे इस व्यक्ति के पास। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका में उसे अवैध प्रवेश के आरोप में पकड़ा गया और फिर भारत को सौंपा गया। परंतु उसके अपराधों की सूची किसी भी छोटे गिरोह से कहीं आगे बढ़ चुकी है—बॉलीवुड स्टार के घर के बाहर गोलियों की आवाज़ से लेकर पंजाब के सबसे चर्चित सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या तक, और मुंबई के प्रभावशाली नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या तक।

सलमान खान के घर अप्रैल 2024 में हुई फायरिंग में अनमोल का नाम सबसे पहले सामने आया था। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का कहना था कि फायरिंग सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित संदेश था, जिसके पीछे अनमोल और विदेश में बैठे उसके साथियों की योजना थी। इसके बाद मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई—जिसने एक बार फिर दिखा दिया कि अनमोल के नेटवर्क की पहुँच कितनी तेज़ और कितनी व्यापक थी। 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसका नाम सामने आया, और तभी से NIA ने उस पर दस लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

अनमोल पर आरोप है कि वह विदेश से बैठे-बैठे भारत में गैंगस्टरों को न केवल धन उपलब्ध कराता था, बल्कि फायरिंग, धमकी, रंगदारी और हत्या जैसे ऑपरेशनों की प्लानिंग में भी सक्रिय भूमिका निभाता था। यही वजह है कि NIA ने उसे सिर्फ एक अपराधी के तौर पर नहीं देखा—बल्कि उस पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा, जो पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका और भारत के बीच फैला हुआ बताया जाता है।

माउंट आबू में पारा शून्य पर जम गया, राजस्थान में ठिठुरन बढ़ी; कई जिलों में बारिश का नया खतरा

(जीएनएस)। राजस्थान की सर्द हवाओं ने इस बार नवंबर में ही अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। अरावली की गोद में बसे माउंट आबू में लगातार चौथे दिन भी रात का तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर अटका रहा—मानो पहाड़ों की सांसें भी जम गई हों। सुबह की धूप के आने से पहले की नीरवता में धरती पर जमी ओस बर्फ का रूप ले लेती है, पेड़ों की पत्तियाँ क्रिस्टल की तरह चमक उठती हैं और आसपास की सड़कों पर एक हल्की-सी जमी परत यह एहसास दिलाती है कि पहाड़ों का असली सर्द मौसम दस्तक दे चुका है।

लेकिन माउंट आबू की इस कड़ाके की ठंड के बीच राजस्थान का बाकी इलाका थोड़ी राहत की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर हिस्सों में दिन के समय मौसम सुहावना रहेगा और धूप की नरमी लोगों को कुछ राहत देगी। हालांकि रातें उत्तर और पश्चिम राजस्थान में लगातार ठिठुराती रहेंगी।

इस बीच मौसम विभाग ने एक नया अलर्ट जारी किया है—21 और 22 नवंबर को उत्तर-पूर्वी राजस्थान के

कई इलाकों में बारिश की संभावना है। यह हल्की फुहारें पड़ते ही तापमान में फिर गिरावट ला सकती हैं और रात की ठंड को और गहरा सकती हैं।

जयपुर का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में सुबह और शाम दोनों समय हल्की ठंडक के साथ हवा में सूखापन महसूस किया जा रहा है। अनुमान है कि अगले दो से तीन दिनों तक जयपुर में मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, सीकर और टोंक जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री के आसपास बने रहने का अनुमान है। यानी दिन की धूप और रात की सर्दी के बीच का अंतर लोगों के लिए एक बार फिर चुनौती बन सकता है।

उत्तर-पश्चिम राजस्थान—चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भी यही मौसम है। सुबह की ठंड रात से उतरकर अभी तक धरती पर बनी रहती है, जबकि दोपहर की धूप थोड़ी राहत देती है। मध्य राजस्थान—जयपुर, अजमेर, जोधपुर—इन क्षेत्रों में रातें ठंडी और दिन हल्के गर्म बने हुए हैं।

दक्षिण राजस्थान—उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा—यहां सर्दी की दस्तक बाकी हिस्सों के मुकाबले नरम है, लेकिन तापमान धीरे-धीरे नीचे उतरना शुरू हो चुका है।

पूर्वी जिलों—भरतपुर, धौलपुर और दौसा—यहां भी मौसम में ठंडक बढ़ने की तैयारी है और रात का तापमान आने वाले दिनों में गिर सकता है।

अच्छी खबर यह है कि फिलहाल किसी प्रकार के तूफान या धूलभरी आंधी की चेतावनी नहीं है। हवा की गति सामान्य बनी हुई है और आसमान 24 नवंबर तक साफ से लेकर हल्का बादली रह सकता है। हालांकि ठंड बढ़ने का एक और संकेत सामने है—उत्तर और उत्तर-पूर्व राजस्थान के कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाने का अनुमान है। कोहरा बहुत घना नहीं होगा, इसलिए दृश्यता या यातायात पर इसका गंभीर असर पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन सुबह-सुबह सड़क पर निकलने वालों को सावधानी बरतनी ही होगी।

राजस्थान में मौसम इस समय दो रंग दिखा रहा है—एक तरफ माउंट आबू की जमा देने वाली ठंड और दूसरी तरफ मैदानों की थोड़ी राहत भरी सुबह। लेकिन दोनों के बीच एक चीज साझा है—सर्दी धीरे-धीरे अपना कब्जा जमा रही है और आने वाले दिनों में तापमान और नीचे उतर सकता है।

मेरठ में पार्टी की रोशनी के बीच सूट-बूट वाला साया, हीरे का हार हवा में समा गया-शातिर चोर की करतूत कैमरों में कैद

(जीएनएस)। मेरठ की जगमगाती शाम, संगीत की गूंज, मेहमानों की हंसी और जश्न का माहौल। ऐसा लगता था मानो शहर की रौनक उस रात एक ही रिसॉर्ट में सिमट आई हो। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के दिल्ली–देहरादून हाईवे पर बने शानदार रिसॉर्ट में पल्लवपुरम फेज-1 के सुभाष बंसल अपने दोनों बेटों के घर बेटियों के जन्म की खुशी में भव्य समारोह आयोजित कर रहे थे। रिश्तेदारों, मित्रों और मेहमानों से भरा हुआ हॉल उत्साह और उल्लास से चमक रहा था।

लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी भीड़, इसी रोशनी के बीच एक साया धीरे-धीरे घूम रहा था—सूट-बूट में सजा-धजा, बिल्कुल सामान्य दिखता हुआ, और फिर भी भीतर से बेहद खतरनाक इरादों वाला।

समारोह में बच्चे को गोद में उठाए मुस्कुराते चेहरे, मिठाई की प्लेटें, कैमरों की फ्लैश—यह सब चलता रहा। उसी दौरान एक अनजान युवक चुपचाप तेज कदमों से अंदर आता है। पूरी तरह फॉर्मल लुक, हाथ पर रखा कोट, और ऐसा व्यक्तित्व कि पहली नजर में कोई शक करने की वजह ही नहीं दिखती। लोग स्वाभाविक रूप से मान बैठे कि वह किसी रिश्तेदार का परिचित होगा। वह आराम से सोफे पर बैठ जाता है, चारों ओर नज़रें घुमाता है, और कुछ देर बाद

बिल्कुल सहजता से उस काउंटर की ओर बढ़ जाता है जहाँ बच्चियों के लिए लाए गए गिफ्ट और डिस्प्ले ज्वेलरी सजाई गई थीं।

CCTV फुटेज में दिखता है कि युवक गोल्ड-क्रीम रंग की डिस्प्ले टेबल के पास रुकता है, अपनी नज़रें चारों ओर तिरछी करता है और फिर ऐसा कदम उठाता है जिसने पूरी पार्टी को हिला दिया। वह ज्वेलरी का बॉक्स खोलता है, अंदर से कीमती हीरों का हार निकालता है और अपने कोट के अन्दर, बाईं बांह के पास, इतनी सफाई से छुपा लेता है कि देखने वाला भी चकित रह जाए।

उसका आत्मविश्वास चौंका देने वाला था—न कोई हड़बड़ाहट, न बेचैनी, न घबराहट। मानो वह यह काम एक बार नहीं, कई बार कर चुका हो।

लेकिन किस्मत और कैमरा दोनों से वह बच नहीं सका। बाहर निकलते समय एक महिला की नज़र उस पर पड़ती है और उसकी हरकत देखकर वह तुरंत शोर मचा देती है — "चोर! चोर!"

कुछ ही सेकंड में जश्न का माहौल भगदड़ में बदल जाता है। लोग युवक की ओर दौड़ते हैं। किश्तों में लाइटें झिलमिलाती हैं, हवा में गूंजता हुआ शोर, भागता हुआ आरोपी—सब मिलकर किसी फिल्मी दृश्य जैसे लगते हैं। लेकिन फिल्मों के विपरीत, यहाँ चोर पकड़ में नहीं आता। वह तेजी से गेट की ओर भागता है और पकड़ में आने से कुछ ही पल पहले अंधेरे में गुम हो जाता है।

रिसॉर्ट में हड़कंप मच जाता है। तुरंत सभी CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं। स्क्रीन पर चोर का चेहरा बार-बार सामने आता है, उसकी चाल, उसकी सावधानी, उसकी सटीक योजना—सब कुछ पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग बन जाता है।

कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह फुटेज को बारीकी से देखते हैं और तुरंत दो विशेष टीमें गठित की जाती हैं। आसपास के सभी मार्गों, दुकानों और हाईवे के कैमरों की फुटेज की जांच शुरू होती है। पुलिस का मानना है कि चेहरा स्पष्ट है, चाल-ढाल, कद-काठी सब साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी दूर नहीं।

रिसॉर्ट में अब भी सन्नाटा है। जहां कुछ घंटे पहले संगीत गूंजता था, आज पुलिस की फुसफुसाहट और CCTV की चमक भर बची है। परिवार बेहद परेशान है—क्योंकि वह हार न केवल महंगा था, बल्कि भावनात्मक रूप से भी कीमती था।

मेरठ वालों के लिए यह मामला एक चेतावनी भी है—

आज के चोर पुराने जमाने की तरह फटे कपड़ों में, चेहरे पर घबराहट लिए नहीं आते। अब वे सूट-बूट पहनते हैं, महंगे परफ्यूम लगाते हैं और बड़ी पार्टियों में सामान्य मेहमान की तरह घुल-मिलकर सबकी आंखों के सामने चोरी कर जाते हैं।

यह वारदात सिर्फ एक हार की चोरी नहीं, बल्कि शहर के लोगों को दिया गया नया सबक है—

चमकते चेहरे के पीछे कौन-सा इरादा छुपा है, ये पहचानना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है।

राजभवन बनाम टीएमसी का तूफ़ान: राज्यपाल और सांसद आमने-सामने, बंगाल की सियासत में मचा ज़बरदस्त घमासान

(जीएनएस)। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा बवंडर लंबे समय से नहीं उठा था, जैसा इन दिनों राज्यपाल सीवी आनंद बोस और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के बीच देखने को मिल रहा है। दोनों ओर से आरोप–प्रत्यारोप, पुलिस थानों में दर्ज कराई गई शिकायतें और मीडिया के सामने लगातार दिए जा रहे बयान इस विवाद को एक ऐसे मुकाम पर ले आए हैं, जहां सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि संवैधानिक गरिमा भी सवालों के घेरे में है। बुधवार को इस टकराव की आग और भड़क गई जब कल्याण बनर्जी खुद हेयर स्ट्रीट थाने पहुंचे और राज्यपाल के खिलाफ भारी धाराओं में शिकायत दर्ज करा दी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, 152, 192, 196 और 353 के तहत दायर की गई इस शिकायत में कहा गया है कि राज्यपाल ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और गैर जिम्मेदाराना बयान देकर राजनीतिक माहौल को भड़काया। वहीं दूसरी ओर, राज्यपाल की ओर से भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 के तहत सांसद के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप फैलाए गए।

विवाद की शुरुआत कुछ दिन पहले तब हुई जब तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि राजभवन के अंदर बम और बंदूकें रखी हुई हैं। यह बयान बंगाल की राजनीति में भूचाल की तरह फैला और राजभवन की प्रतिष्ठा पर सीधे प्रहार के रूप में देखा गया। आरोप गंभीर था और प्रतिक्रिया भी उतनी ही गंभीर रही। अगले ही दिन राजभवन ने बम निरोधक दस्ते, सीआईएसएफ और राज्य पुलिस को बुलाकर अचानक तलाशी अभियान चलाया। मीडिया को भी बुलाया गया ताकि हर कदम सार्वजनिक रहे। लेकिन तलाशी के बाद कोई हथियार या गोला–बारूद नहीं मिला और राजभवन ने इसे झूठा प्रचार बताते हुए कहा कि सांसद को पूरे राज्य से माफी मांगनी चाहिए। इतने बड़े सार्वजनिक अभियान के बाद विवाद शांत होने के बजाय और तेज हो गया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि वे कभी अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं और उन्होंने जो कहा था, वही सच है। इसी तनावपूर्ण माहौल में तृणमूल सांसद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर मामले को और गर्मा दिया। शिकायत में राज्यपाल पर यह आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल करके राजनीति को गरमाया और सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल बनवाया। दिलचस्प बात यह है कि शिकायत में सीवी आनंद बोस का नाम, पता और पिता का नाम तो दर्ज किया गया है, लेकिन 'राज्यपाल' के पद का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मामला सियासी कम और व्यक्तिगत टकराव ज़्यादा बनता जा रहा है।

राज्यपाल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राजभवन किसी के लिए कोई बंद कमरा नहीं है। वह पत्रकारों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के लिए खुला रहेगा और अगर कोई यह साबित कर दे कि अंदर हथियार हैं, तो यह जनता के लिए जानने योग्य सच होगा। अगर नहीं हैं, तो राजभवन की गरिमा पर लगाए गए आरोपों की कीमत जिम्मेदार लोगों को चुकानी होगी। इसी बीच भाजपा ने भी इस पूरे मामले में प्रवेश कर लिया और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल पर तीखे शब्दों में हमला बोल दिया। अधिकारी ने कहा कि तृणमूल एक खतरनाक पार्टी है और राज्यपाल के खिलाफ की गई कार्रवाई भी उतनी ही खतरनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वे केंद्रीय एजेंसियों से शिकायत करेंगे। उन्होंने राजभवन में मीडिया के सामने तलाशी को 'पारदर्शिता' का कदम बताते हुए कहा कि इससे टीएमसी द्वारा फैलाए गए भ्रम का पर्दाफाश हो गया है। राज्यपाल की ओर से मतदाता सूची सुधार पहल यानी एसआईआर का खुलकर समर्थन करना भी तृणमूल और राजभवन के बीच बढ़ते तनाव की एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि टीएमसी शुरू से ही इस पहल का विरोध कर रही है।

जैसे–जैसे बंगाल विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, यह टकराव किसी बड़े राजनीतिक संघर्ष का संकेत बनता जा रहा है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख और सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद की यह भिड़ंत अब सिर्फ बयानबाज़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस और कानूनी कार्रवाई तक पहुंच चुकी है। माहौल ऐसा है कि हर नया दिन इस विवाद में एक नया मोड़ जोड़ रहा है और बंगाल की राजनीतिक हवा में एक अजीब-सी बेचैनी महसूस की जा रही है। आगे इस घमासान का अंत किस दिशा में होगा, यह फिलहाल कोई नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में इस विवाद की लपटें और भी तेज होंगी और बंगाल की राजनीति में यह घटना लंबे समय तक याद रखी जाएगी।

दिल्ली ब्लास्ट की गूँज में 'संदेह' की चोट झेलते कश्मीरी: उमर अब्दुल्ला बोले-कुछ गुनहगारों की वजह से पूरी आबादी कटघरे में खड़ी कर दी गई

(जीएनएस)। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए दर्दनाक धमाके ने देश को झकझोर दिया था। विस्फोट में 13 लोगों की मौत और कई घायल हुए, और सदमे की इस लहर ने सबसे ज्यादा असर उस जगह पर छोड़ा, जहां से संदिग्धों का नाम जुड़ा—जम्मू-कश्मीर। जैसे ही जांच में सामने आया कि मुख्य संदिग्ध पुलवामा निवासी डॉ. उमर उन नबी था और उसके दो साथी भी कश्मीर से थे, राष्ट्रीय मीडिया से लेकर आम लोगों की निगाहें अचानक पूरे कश्मीर पर टिक गईं। इस माहौल को सबसे पहले शब्द देने वाले जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने, जिन्होंने कुलगाम में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस देश में अब कश्मीर का नाम आते ही संदेह की धुंध फैल जाती है और निर्दोषों को अपराधियों की तरह देखा जाने लगा है। उन्होंने पीड़ा भरे स्वर में कहा कि कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता ने पूरी आबादी को शक के घेरे में डाल दिया है। वे बोले कि कश्मीर का हर निवासी कहीं बाहर जाता है तो उसे डर लगता है कि कहीं सिर्फ पहचान के आधार पर उसे आरोपी न बना दिया जाए। उन्होंने साफ कहा कि कई कश्मीरियों ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में जाना लगभग बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं किसी की नजर उन पर न टिक जाए और उन्हें किसी अपराध से जोड़ दिया जाए जिसका उनसे कोई लेना-देना ही नहीं।

उमर अब्दुल्ला का दर्द तब और गहरा हो गया जब उन्होंने कहा कि वर्तमान माहौल में माता-पिता भी बच्चों को कश्मीर से बाहर पढ़ने या काम करने भेजने से डर रहे हैं। वे बोले कि जिस समाज में सिर्फ आपकी पहचान देखकर आप पर उंगलियाँ उठने लगें, वहाँ सामान्य जीवन जीने की कल्पना ही कठिन हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सच्चाई कड़वी है, लेकिन यही आज की हकीकत है कि कुछ लोगों की हिंसा की सजा पूरे जम्मू-कश्मीर को भुगतनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जम्मू-कश्मीर नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाना तक अपराध जैसा महसूस करवाया जा रहा है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि सुरक्षा कम होने पर वे भी सोचते हैं कि क्या गाड़ी निकालें या नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन उन्हें रोककर पूछताछ करने लगे और सिर्फ पहचान के कारण शक जताए।

धमाके की जांच इस समय कई एजेंसियाँ कर रही हैं—दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, एनआईए और क्राइम ब्रांच। संदिग्धों में डॉक्टर, पढ़े-लिखे लोग और सफेदपोश मॉड्यूल के सदस्य शामिल बताए गए हैं, जिसने इस घटना को और भी पेचीदा बना दिया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि कुछ गुनहगारों की पहचान पूरे समाज की पहचान नहीं होती। उन्होंने याद दिलाया कि आतंकवाद को कोई धर्म इजाजत नहीं देता और न ही कश्मीर का हर व्यक्ति आतंकवादियों के साथ खड़ा है। उनका कहना था कि जिस तरह हर राज्य में अपराध करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनके आधार पर पूरे राज्य को अपराधी नहीं कहा जाता, उसी तरह जम्मू-कश्मीर के निर्दोष लोगों को भी इस तरह संदेह में घसीटना बेहद अनुचित है।

उन्होंने अपने भाषण में दिल्ली ब्लास्ट की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि यह मानवता के खिलाफ अपराध है और इसके दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी समझना होगा कि कश्मीर का हर युवक, हर माता-पिता और हर परिवार आतंकवाद का समर्थक नहीं है।